

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तराखण्ड.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 30 मई, 2013

विषय:- वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के आयोजनागत पक्ष की जिला सेक्टर योजना "भवन निर्माण एवं बिजली पानी व्यवस्था" (राजस्व पक्ष) में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तराखण्ड के पत्रांक नि0- 2241/3-4 (जि0यो0) दिनांक 30.05.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत संचालित आयोजनागत पक्ष की जिला सेक्टर योजना 'भवन निर्माण एवं बिजली पानी व्यवस्था' (राजस्व पक्ष) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष ₹ 2,00,00,000/- (₹ दो करोड़ मात्र) व्यय किये जाने के लिए आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 एवं राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या-631/362-वा0जि0यो0/ रा0यो0आ0/2012 दिनांक 27 मई, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा बांझित सूचनाएँ एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्चोरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का संक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय। धनराशि का आहरण एवं व्यय अनुमोदित परिब्यय के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। साथ ही पूर्व अवमुक्त धनराशियों के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा इसके अतिरिक्त योजना की प्रगति तथा उद्देश्यों की पूर्ति संतोषजनक होने पर ही धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।
3. यह संज्ञान में आया है कि वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त भी वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो.
4. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.
5. व्यय के सम्बन्ध में निर्धारित बी0एम0-प्रपत्र पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय।
6. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.
7. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.
8. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
9. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

11. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है, जो संलग्न है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।
 12. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति को राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-631/362-वा0जि0यो0/ रा0यो0आ0/2012 दिनांक 27 मई, 2013 / जिला योजना समिति द्वारा निर्धारित किये गये भौतिक लक्ष्य को प्राप्त किये जाने हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
 13. योजना के अन्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध बजट प्रावधान अनुमोदित परियोजना से कम है, जिस कारण निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष आवश्यकता के आधार पर कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करते हुये कार्य सम्पन्न कराये जाय। अनुमोदित परियोजना के सापेक्ष अवशेष बजट की मांग अनुपूरक बजट के माध्यम से बाद में की जायेगी।
 14. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथावश्यकता अनुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1638/XXX-1-12(25)2011, दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।
 15. आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
 16. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति में अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय और यह सुनिश्चित किया जाये कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाय और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।
- 2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के स्वीकृत आय-व्यय के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 91- जिला सेक्टर योजना-02 भवन निर्माण एवं बिजली पानी व्यवस्था हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामों डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु सम्बन्धित जिले की Online Budget Allotment हार्ड कापी भी संलग्न है :-

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम			
		भवन निर्माण एवं बिजली पानी की व्यवस्था			
		मानक मद			
		25- लघु निर्माण कार्य	26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	29-अनुरक्षण	योग
1	नैनीताल	750	0	750	1500
2	ऊधमसिंह नगर	0	200	1613	1813
3	अल्मोड़ा	900	0	900	1800
4	बागेश्वर	605	200	707	1512
5	पिथौरागढ़	1259	0	1248	2507
6	चम्पावत	0	0	0	0
7	देहरादून	440	100	860	1400
8	टिहरी	0	0	857	857
9	पौड़ी गढ़वाल	849	400	873	2122
10	चमोली	1241	0	358	1599
11	रूद्रप्रयाग	679	700	319	1698
12	उत्तरकाशी	1045	342	1225	2612
13	हरिद्वार	232	58	290	580
	योग	8000	2000	10000	20000

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ दो करोड़ मात्र)

- 3- ये आदेश वित्त विभाग (अनुभाग-1) के शासनादेश सं०- 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्दन)
अपर सचिव

तिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
7. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड.
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य, देहरादून.
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
13. गार्ड फाईल.

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रग)

अपर सचिव